

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/ 6701

दिनांक : 14/11/22

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विषय : Diversion of 466.592 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport kota, District-Bundi in the state of Rajasthan . (Proposal No.FP/RJ/Others/150590/2021)

संदर्भ : आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 12.09.2022 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 12.09.2022 के संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली के पत्रांक 8-05/2022-एफसी दिनांक 05.09.2022 द्वारा चाही गयी बिन्दुओं की सूचना उप वन संरक्षक बून्दी ने पत्रांक 12019 दिनांक 14.11.2022 से बिन्दुवार तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो कि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	EDS raised by MoEF & CC New Delhi	Reply
1	The State Govt. was requested to provide a NOC from Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) for the forest land under diversion. Instead of submission of NOC a copy of the letter written by PGCIL to the User Agency for depositing of estimate of Rs. 54,78,15,921/- for shifting of transmission line is furnished. It is again requested that NOC from PGCIL be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड कोटा से प्राप्त एनओसी कार्यालय प्रेषित की हैं, जो संलग्न है। (Annexure-1)
2	Shifting plan for the proposed transmission line by Power Grid Corporation of India Limited does not give clear picture about 'To & Fro' passage of the transmission line to be shifted. Therefore, KML file/Shape file with area details as per plan of shifting of the transmission line is required.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित पावर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड कोटा की ट्रांसमिशन लाईन का शिफ्टिंग प्लान/केएमएल फाईल कार्यालय में प्रेषित की है। जो संलग्न (Annexure-2) है।
3	In response to the observation raised vide Sr no (iv) for Ministry's letter dated 17.06.2022 it is informed that 33,408 ha land is recorded in the name of Urban Improvement Trust, Kota and it is not any notified deemed forest whereas the digital forest boundary available on Rajasthan forest department website shows that	1- MOEF के पत्र दिनांक 05.9.2022 के साथ संलग्न (Annexure-3) में टी (T) शेप का पोलीगन (KML) राजस्व रिकार्ड व वन विभाग के रिकार्ड अनुसार मिसप्लेस हुआ है। T शेप में दिया गया पोलीगन वास्तव में राजस्व रिकार्ड व वन विभाग रिकार्ड अनुसार L शेप में है। जिसका विवरण Annexure -4 and Annexure-5 में अंकित है। 2- राजस्व व वन विभाग रिकार्ड अनुसार L शेप का पोलीगन ग्राम केथूदा के खसरा नं. 855/550 एवं


	<p>some part of Non-forest land in the instant proposal is falling within the forest boundary. In this regard, a copy the extract portion of Google imagery is enclosed in Annexure for ready reference. Further the State Government in response to a specific query at sr no. (v) of letter dated 17.06.2022 has mentioned that the digital boundary of the forest land is correct. The above details are therefore contradictory to each other. This need clarification with supporting documents from Govt. of Rajasthan.</p>	<p>845/544 से बना है जो जमाबंदी (Annexure-7) के अनुसार नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज है। यह वन सीमा से बाहर है।</p> <p>3- MOEF के पत्र दिनांक 05.09.2022 के साथ संलग्न T शेष के अतिरिक्त प्रदर्शित दो पोलीगन में भी ब्ल्यू लाईन, वन सीमा (ग्रीन लाईन) के ऊपर आंशिक रूप से ओवरलेप है, जबकि वनखण्ड पत्रावली में उपलब्ध नक्शों तथा राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध नक्शे अनुसार मौके पर ओवरलेपिंग नहीं है। अतः राजस्थान वन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटल वन सीमा पूर्ण रूप से सही नहीं है (Annexure - 4 and 5) की स्थिति अनुसार ओवरलेप नहीं हैं एवं वन सीमा से बाहर है। वन विभाग (वनखण्ड नक्शा Annexure-6) व राजस्व रिकार्ड के अनुसार (Annexure-4) प्रस्तावित एयर पोर्ट की कुल भूमि 500 हैक्टर है जिसमें से 466.592 हैक्टर वन भूमि व 33.408 हैक्टर गैर वन भूमि है (L शेष एवं शेष 02 पोलीगन का क्षेत्र है) जो वन सीमा से बाहर है।</p>
4	<p>Integrated Regional Office (IRO), Jaipur in Site Inspection Report (SIR) has pointed out that the areas proposed for compensatory afforestation are infested with Prosopis juliflora and Lantana. There is no provision seen for removal of these invasive species in CA plan and without removal of these invasive weeds it will be difficult to plant 1000 seedling/hectare. In view of this the State Govt. may examine the issue and take necessary action accordingly.</p>	<p>प्रस्तावित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण-DFL में जूलीफ्लोरा एवं लेण्टाना (खरपतवार) की संघनता होने के कारण पृथक-पृथक प्रस्तावित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण-DFL में खरपतवार की संघनता प्रतिशत के अनुसार सीए प्लान में संशोधन करके जूलीफ्लोरा एवं लेण्टाना (खरपतवार) के हटाने की राशि ली गई है संशोधित एस्टीमेट संलग्न है। (Annexure-8)</p>
5	<p>The IRO, Jaipur in their SIR also reported that two fragmented patches of forest land at Northern side of the proposed airport are of about 33.5 ha. and 137.01 ha. are left and will be prone to encroachment. It has been proposed that the User Agency may construct boundary wall for these two patches the State Govt. may provide comments in this regard.</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत Undertaking अनुसार उल्लेखित दोनों पैचेज हेतु राज्य सरकार अपने व्यय पर पक्की दीवार निर्माण का कार्य कराएगी। प्रति संलग्न (Annexure-9)</p>
6	<p>It is observed that the Ramgarh-Vishdhari the newly notified 52nd Tiger Reserve in the country came into existence vide Notification dated 16.05.2022. The CWLW Govt. of Rajasthan vide letter dated 25.05.2022 had earlier reported that the proposed airport is out of Eco-sensitive zone of the Mukundara</p>	<p>वांछित टिप्पणी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर कार्यालय से की जानी है इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।</p>

<p>Hills Tiger Reserve and located at distance of 7.2 km from National Chambal Sanctuary. Now as per comments/observation made by the integrated Regional office (IRO), Jaipur the entire area proposed for diversion falls within buffer of Ramgarh-vishdhari Tiger Reserve. Therefore, the comments of CWLW, Govt. of Rajasthan keeping in view the newly notified tiger reserve are required to be submitted.</p>	
--	--

अतः उप वन संरक्षक बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सेट-

भवदीय


(महेश चन्द गुप्ता)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, बून्दी को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक :

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

E-Mail:- def.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823

दिनांक : 14/11/22

नांक एफ()एफसीए/उवसं/2022/ 12019

निमित्त:

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Subject: Diversion of 466.592 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan. Proposal No.FP/RJ /Others/ 150590/2021.


Ref.: Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi File No. 8-05/2022-FC Dated 05.9. 2022. एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र क्रमांक 466 दिनांक 28.9.2022. एवं 555 दिनांक 11.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रस्तावित Diversion of 466.592 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 05.9.2022 की बिन्दुवार पालना प्रयोक्ता एजेन्सी से संबंधित पालना कार्यालय में प्रेषित की है एवं इस कार्यालय से संबंधित पालना निम्नानुसार है जो आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है:-

S. No.	EDS raised by MoEF&CC New Delhi	Reply
1.	The State Govt. was requested to provide a NOC from Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) for the forest land under diversion. Instead of submission of NOC, a copy of the letter written by PGCIL to the User Agency for depositing of estimate of Rs.54,78,15,921/- for shifting of transmission line is furnished. It is again requested that NOC from PGCIL be submitted.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड कोटा से प्राप्त एनओसी कार्यालय प्रेषित की हैं, जो संलग्न है। (Annexure-1)
2.	Shifting plan for the proposed transmission line by Power Grid Corporation of India Limited does not give clear picture about 'To & Fro' passage of the transmission line to be shifted. Therefore, KML file/ Shape file with area details as per plan of shifting of the transmission line is required.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित पावर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड कोटा की ट्रांसमिशन लाईन का शिफ्टिंग प्लान/केएमएल फाईल कार्यालय में प्रेषित की है। संलग्न (Annexure-2)

<p>in response to the observation raised vide Sr no (iv) of Ministry's letter dated 17.06.2022, it is informed that 33.408 ha land is recorded in the name of Urban Improvement Trust, Kota and it is not any notified deemed forest whereas the digital forest boundary available on Rajasthan forest department website shows that some part of Non-forest land in the instant proposal is falling within the forest boundary. In this regard, a copy the extract portion of Google imagery is enclosed in Annexure for ready reference. Further the State Government in response to a specific query at sr no. (v) of letter dated 17.06.2022 has mentioned that the digital boundary of the forest land is correct. The above details are therefore contradictory to each other. This need clarification with supporting documents from Govt. of Rajasthan.</p>	<p>1- MOEF के पत्र दिनांक 05.9.2022 के साथ संलग्न Annexure -3 में टी (T) शेप का पोलीगन (KML) राजस्व रिकार्ड व वन विभाग के रिकार्ड अनुसार मिसप्लेस हुआ है। T शेप में दिया गया पोलीगन राजस्व रिकार्ड व वन विभाग रिकार्ड अनुसार L शेप में है। जिसका विवरण Annexure -4 and Annexure-5 में अंकित है।</p> <p>2- राजस्व व वन विभाग रिकार्ड अनुसार L शेप का पोलीगन ग्राम केथूदा के खसरा नं. 855/550 एवं 845/544 जमाबंदी (Annexure-7) के अनुसार नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज है। जो वन सीमा से बाहर है।</p> <p>3- T शेप के अतिरिक्त प्रदर्शित दो पोलीगन में भी ब्ल्यू लाईन, वन सीमा (ग्रीन लाईन) के ऊपर आंशिक रूप से अवरलेप है, जो वास्तव में वन विभाग व राजस्व रिकार्ड (Annexure-4 and 5) की स्थिति अनुसार ओवरलेप नहीं हैं एवं वन सीमा से बाहर है। वन विभाग (वनखण्ड नक्शा Annexure-6) व राजस्व रिकार्ड के अनुसार (Annexure-4) प्रस्तावित एयर पोर्ट की कुल भूमि 500 हैक्टर है जिसमें से 466.592 हैक्टर वन भूमि व 33.408 हैक्टर गैर वन भूमि है (L शेप एवं शेप 02 पोलीगन का क्षेत्र है) जो वन सीमा से बाहर है।</p>
<p>4. Integrated Regional Office(IRO), Jaipur in Site Inspection Report (SIR) has pointed out that the areas proposed for Compensatory Afforestation are infested with Prosopis juliflora and Lantana. There is no provision seen for removal of these invasive species in CA plan and without removal of these invasive weeds it will be difficult to plant 1000 seedling/hectare. In view of this, the State Govt. may examine the issue and take necessary action accordingly</p>	<p>प्रस्तावित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण-DFL में जूलीफ्लोरा एवं लेण्टाना (खरपतवार) की संघनता होने के कारण प्रथक-प्रथक प्रस्तावित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण -DFL में खरपतवार की सघनता प्रतिशत के अनुसार सीए प्लान में संशोधन करके जूलीफ्लोरा एवं लेण्टाना (खरपतवार) के हटाने की राशि ली गई है संशोधित एस्टीमेट संलग्न है। (Annexure-8)</p>
<p>5. The IRO, Jaipur in their SIR also reported that two fragmented patches of forest land at Northern side of the proposed airport are of about 33.5 ha. and 137.01 ha. are left and will be prone to encroachment. It has been proposed that the User Agency may construct boundary wall for these two patches The State Govt. may provide comments in this regard.</p>	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत Undertaking संलग्न है। (Annexure-9)</p>
<p>6. It is observed that the Ramgarh -Vishdhari the newly notified 52nd Tiger Reserve in the country came into existence vide Notification dated 16.05.2022. The</p>	<p>वांछित टिप्पणी मुख्य वन जीव प्रतिपालक जयपुर कार्यालय से की जानी है इस कार्यालय से संबधित नहीं है।</p>


(डॉ. टी. मोहनराज)
 उष वन संरक्षक
 बन्दी

CWLW, Govt. of Rajasthan vide letter dated 25.05.2022 had earlier reported that the proposed airport is out of Eco- sensitive zone of the Mukundara Hills Tiger Reserve and located at distance of 7.2 Km from National Chambal Sanctuary. Now as per comments/ observations made by the Integrated Regional Office(IRO), Jaipur the entire area proposed for diversion falls within buffer of Ramgarh-Vishdhari Tiger Reserve. Therefore, the comments of CWLW, Govt. of Rajasthan keeping in view the newly notified tiger reserve are required to be submitted.

भवदीय

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Say
(टी मोहनराज)
उप वन संरक्षक
बून्दी

क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2022/

दिनांक :

प्रतिलिपि अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(डॉ. टी मोहनराज)
उप वन संरक्षक
बून्दी